शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 06-13 जून 2022 मूल्य पांच रूपए

निर्दलीय विधायकों के शामिल होने से भाजपा की गुटबंदी आयी खुलकर सामने

शिमला/शैल। प्रदेश विधानसभा में दहेरा और जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो गये हैं। दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को भाजपा में शामिल होने से पहले अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहिये था। ऐसा न करने पर विधानसभा अध्यक्ष इनके खिलाफ कारवाई करते हुये इनकी सदस्यता रद्द करते हुये इन्हें तीन वर्ष तक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर सकता है। ऐसा दल बदल कानून में प्रावधान है। ऐसा अध्यक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान और किसी की याचिका पर दोनों रूपों में किया जा सकता है। कांग्रेस ने इस संबंध में याचिका दायर करने की भी बात की है। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के स्टैंड पर प्रतिक्रिया देते हुये यह कहा है कि कांग्रेस की मांग पर यह विधायक सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। भाजपा की इस प्रतिक्रिया से पता चल जाता है कि नियमों कानूनों का कितना सम्मान यह पार्टी करती है और इसका चाल चरित्र और चेहरा कहां दूसरों से भिन्न है जिसका दावा किया जाता रहा है।

इसके अतिरिक्त इसका दूसरा पक्ष यह रहा है कि देहरा से पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और जोगिन्दर नगर से पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ने चुनाव लड़ा था। वो धूमल के विश्वस्त माने जाते हैं। गुलाब सिंह तो अनुराग ठाकुर के ससुर हैं। धूमल को योजनाबद्ध तरीके से हराया गया था यह सुरेश भारद्वाज और जगत प्रकाश नड्डा के ब्यानों से स्पष्ट हो चुका है। जंजैहली प्रकरण में धूमल को यह ब्यान देने के कगार पर पहुंचा दिया गया था कि ''सरकार चाहे तो उनकी सी.आई.डी. जांच करवा ले। इसके बाद मानव भारती विश्वविद्यालय प्रकरण में जिस तरह का ब्यान पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का राजेंद्र राणा के पत्रों पर आ गया था उससे जयराम सरकार के रिश्ते धूमल के साथ और स्पष्ट हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जिस तरह से मंच पर नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अनुराग का नाम तक नहीं लिया है। उससे राजनीतिक रिश्तों का सच और स्पष्ट हो जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर जसवां की एक जनसभा में अनुराग और जयराम के बीच हुआ संवाद भी

इसी सबकी पुष्टि करता है।

रविंद्र रवि और होशियार सिंह में से जयराम और उसके मंत्री किसको अधिमान देते हैं यह देहरा में महेंद्र सिंह ठाकुर की एक जनसभा में सामने आ ही चुका है। यही नहीं जब किसी कार्यकर्ता ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को लेकर शांता कुमार के नाम एक पत्र लिखा था तब इस पत्र को लेकर रविंद्र रवि के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया था। जब चुनाव हारने के बाद भी भाजपा विधायकों के बहुमत ने धूमल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी तब कुटलैहड के विधायक वीरेंद्र कंवर में धूमल के लिये अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। अब इसी वीरेंद्र कंवर के खिलाफ भरी जनसभा ने इसी निर्दलीय विधायक ने अति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। एक तरह से यह भाषा पूरी सरकार के खिलाफ थी। वीरेंद्र कंवर ने इसे मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात की थी और तब मुख्यमंत्री ने एक बैठक में होशियार सिंह का अभिवादन तक अस्वीकार करके मामले को वहीं खत्म करने का प्रयास किया था।

लेकिन अब जिस तरह से स्थानीय इकाइयों, संबंधित मंत्रियों क्षेत्र के सांसद मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को विश्वास में लिये बिना इन निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया है वह राजनीतिक भाषा में धूमल खेमे के लिये सीधी चुनौती हो जाती है। राजनीतिक विश्लेष्कों के अनुसार आने वाले दिनों में धूमल और जयराम -नड्डा दो खेमों में खुलकर वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जायेगी। क्योंकि इस समय जयराम और नड्डा ने धूमल खेमे को पूरी तरह हाशिये पर धकेल दिया है। इसका असर 2024 में अनुराग के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि यहीं से राज्यसभा सांसद डॉ. सिकन्दर भी धूमल खेमे के लिये एक सरप्राईज ही रहा है। इस परिदृश्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खेमा आगे क्या कदम चलता है।

अब नागरिक आपूर्ति विभाग की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने के लगे आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही खरीदो में पारदर्शिता लाने के लिये ई टेंडर प्रणाली अपना रखी है। इसके लिए एक ई-पोर्टल तैयार किया गया है। जो भी सामान किसी विभाग ने खरीदना होता है उसका ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किया जाता है। इच्छुक बोली दाता उसी प्रणाली में अपना टेंडर भेज देते हैं। बहुत सारे मामलों में टेक्निकल और फाईनाशियल निविदायें अलग-अलग भेजी जाती है। यह निविदायें मिलने पर विभाग पहले टेक्निकल निविदा को खोलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सारी निविदायें तकनीकी तौर पर सही हैं। जो निविदा तकनीकी आधार पर सही नहीं पायी जाती है उसकी वित्तिय निविदा नहीं खोली जाती है। जो निविदा तकनीकी रूप से सही नहीं पायी जाती है उसके कारण भी ई-पोर्टल पर जारी किये जाते हैं। वित्तीय निविदा में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है क्योंकि हर बोली दाता का यह जानने का अधिकार रहता है कि किस आधार पर उसे योग्य नहीं पाया गया। यह भी अधिकार रहता है कि वह विभाग के सामने अपना पक्ष रख सके।

स्मरणीय है कि नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एक करीब 25 करोड़ की खरीद के लिये ई-पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित किये गये थे। यह टेंडर YRFP के अनुसार 28-4-2022 को खोले जाने थे। लेकिन इनके खोलने का समय बदल दिया गया और इसकी कोई पूर्व जानकारी पोर्टल पर नहीं डाली गयी। इसमें एक लिंकवैल टेलीसिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी टेंडर डाला था। इसे तकनीकी टेंडर खोलने के बाद अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इस अस्वीकार के कोई भी कारण संबंधित कंपनी को नहीं बताये गये और ना ही ई-पोर्टल पर लोड किये गये जबकि कंपनी को यह जानने का अधिकार था। इस संबंध में कंपनी ने सभी संबद्ध अधिकारियों से यह कारण जानने का परा प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है।

अब कंपनी में 7-6-2022 को नागरिक आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखकर इसकी जांच किये जाने की मांग की है। मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही लोकायुक्त, प्रधान सचिव नागरिक आपूर्ति वित्त, आईटी और लीगल सैल को भी इसकी प्रतियां भेजी हैं। सूत्रों के मुताबिक कहीं से भी कोई कारवाई सामने नहीं आयी है। जबकि इससे पहले हर खरीद में पूरी पारदर्शिता अपनायी जाती रही है। जिस कंपनी को काम दिया गया है उसे उत्तर प्रदेश एक करोड़ का जुर्माना लगा चुका है। महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकारें भी अप्रसन्नता व्यक्त कर चुकी हैं। इसी परिदृश्य में हिमाचल का मामला रोचक हो जाता है इसलिये इसे पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

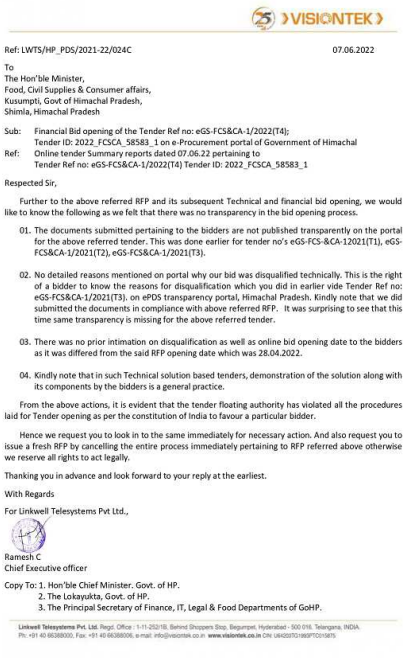

VISIONTEK

Ref: LWTS/HP_PDS/2021-22/024C 07.06.2022

To
The Hon'ble Minister,
Food, Civil Supplies & Consumer affairs,
Kusumpti, Govt of Himachal Pradesh,
Shimla, Himachal Pradesh

Sub: Financial Bid opening of the Tender Ref no: eGS-FCS&CA-1/2022(T4);
Tender ID: 2022_FCSCA_58583_1 on e-Procurement portal of Government of Himachal
Ref: Online tender Summary reports dated 07.06.22 pertaining to
Tender Ref no: eGS-FCS&CA-1/2022(T4) Tender ID: 2022_FCSCA_58583_1

Respected Sir,

Further to the above referred RFP and its subsequent Technical and financial bid opening, we would like to know the following as we felt that there was no transparency in the bid opening process.

01. The documents submitted pertaining to the bidders are not published transparently on the portal for the above referred tender. This was done earlier for tender no's eGS-FCS-&CA-12021(T1), eGS-FCS&CA-1/2021(T2), eGS-FCS&CA-1/2021(T3).

02. No detailed reasons mentioned on portal why our bid was disqualified technically. This is the right of a bidder to know the reasons for disqualification which you did in earlier vide Tender Ref no: eGS-FCS&CA-1/2021(T3). on ePDS transparency portal, Himachal Pradesh. Kindly note that we did submitted the documents in compliance with above referred RFP. It was surprising to see that this time same transparency is missing for the above referred tender.

03. There was no prior intimation on disqualification as well as online bid opening date to the bidders as it was differed from the said RFP opening date which was 28.04.2022.

04. Kindly note that in such Technical solution based tenders, demonstration of the solution along with its components by the bidders is a general practice.

From the above actions, it is evident that the tender floating authority has violated all the procedures laid for Tender opening as per the constitution of India to favour a particular bidder.

Hence we request you to look in to the same immediately for necessary action. And also request you to issue a fresh RFP by cancelling the entire process immediately pertaining to RFP referred above otherwise we reserve all rights to act legally.

Thanking you in advance and look forward to your reply at the earliest.

With Regards

For Linkwell Telesystems Pvt Ltd.,

Ramesh C
Chief Executive officer

Copy To: 1. Hon'ble Chief Minister. Govt. of HP.
2. The Lokayukta, Govt. of HP.
3. The Principal Secretary of Finance, IT, Legal & Food Departments of GoHP.

Linkwell Telesystems Pvt. Ltd. Regd. Office : 1-11-252/18, Behind Shoppers Stop, Begumpet, Hyderabad - 500 016. Telangana, INDIA.
Ph: +91 40 66388000, Fax: +91 40 66388006, e-mail: info@visiontek.co.in www.visiontek.co.in CIN: U64200TG1993PTC015875

राष्ट्रपति ने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया

शिमला/शैल। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल

राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर उनके साथ उपस्थित थे। अटल टनल मनाली को दुर्गम लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ती है।

राष्ट्रपति ने हेलीपैड के समीप सिसु झील, चंद्रभागा नदी, जल प्रपात तथा घाटी की खूबसूरत वादियों में गहरी रुचि दिखाई।

इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी, देश की प्रथम महिला सविता कोविन्द और उनकी पुत्री भी उपस्थित थीं।

इससे पहले, राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के सिसु हेलीपैड आगमन पर उनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पारम्परिक थंका पेटिंग भेंट की।

अटल टनल के साउथ पोर्टल पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), प्रोजेक्ट योजक के मुख्य अभियन्ता जितेंद्र प्रसाद ने अटल टनल के निर्माण और मनाली-लेह मार्ग पर भविष्य में बनने वाली अन्य महत्वपूर्ण सुरंगों के निर्माण के बारे में भी जानकारी दी।

इसके उपरान्त, राष्ट्रपति के प्रदेश में दो दिवसीय प्रवास के सम्पन्न होने पर उनको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू और प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन, भरत खेड़ा ने मनाली के सासे हेलीपैड पर गरिमापूर्ण विदाई दी।

संत रविदास की शिक्षाएं वर्तमान में अधिक प्रासंगिक:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के आदर्श और विचार पूर्ण मानव समाज के हित

व कल्याण के लिये थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं समाज को जोड़ने वाली हैं और आज अधिक प्रासंगिक है।

राज्यपाल कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल में भदरोआ स्थित डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम में श्री गुरु रविदास निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने एमकेएम वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल के छात्रवास का लोकार्पण भी किया।

उन्होंने कहा कि भगवान श्री ष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि धर्म की जब-जब ग्लानि होती है, तब तक किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि समाज जब गलत रास्ते पर चलता है तो ऐसे अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि संतों की सीख सब लोगों व समाज के लिए होती है। वह जो आचरण करते हैं, उस पर किसी विशिष्ट समुदाय का अधिकार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उनके विचार होते हैं।

राज्यपाल ने डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्कूल के माध्यम से शिक्षा का जो कार्य उनके माध्यम से किया जा रहा है वह सराहनीय है।

इससे पहले, राज्यपाल ने संत रविदास मंदिर में माथा टेका।

इस अवसर पर, श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरि जी ने राज्यपाल को सम्मानित किया।

शिमला में आयोजित होगा अन्तरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव

शिमला/शैल। साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के प्रवक्ता ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं साहित्य अकादमी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन 16-18 जून 2022 को शिमला में कला और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है।

गेयटी हेरिटेज संस्कृति परिसर, टाउन हाल व रिज क्षेत्र आदि स्थानों पर आयोजित हो रहे इस साहित्य उत्सव का उद्घाटन सत्र 16 जून 2022 को प्रात: 10 बजे से 12 बजे के बीच गेयटी थियेटर के मुख्य सभागार में होगा, जिसमें संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल एवं मीनाक्षी लेखी और आंध्रप्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन उपस्थित रहेंगे।

किसी भी देश का साहित्य वहाँ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करता है। ऐसे साहित्यिक महोत्सव के आयोजन से समस्त साहित्यिक रंगों का प्रतिनिधित्व परिलक्षित होता है। इन साहित्यिक महोत्सवों में देश के कई प्रख्यात विद्वान एकत्रित होते हैं, जिससे उस क्षेत्र के कई युवा तथा उभरते लेखकों एवं साहित्य प्रेमियों को अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि संस्कृति मंत्रालय तथा साहित्य अकादमी द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में भारत सहित 15 देशों के 425 से अधिक लेखक, विद्वान, अनुवादक, फिल्मकार, पत्रकार एवं कलाकार भाग ले रहे हैं, जो 64 कार्यक्रमों में 60 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्मेष - अभिव्यक्ति का उत्सव शीर्षक से आयोजित हो रहा यह उत्सव देश का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है।

इस उत्सव में परिचर्चा, प्रस्तुति, कहानी एवं कविता-पाठ में विविध विषयों पर विचार विमर्श होगा। कुछ मुख्य विषयों के शीर्षक हैं-साहित्य और सिनेमा, विश्व की कालजयी कृतियॉ और भारतीय लेखन, आदिवासी लेखन, एलजीबीटीक्यू लेखकों का लेखन, मीडिया और साहित्य, भक्ति साहित्य और अनुवाद के माध्यम से सांस्कृतिक एकता आदि। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक शाम को सोनल मानसिंह द्वारा भरतनाटयम, पी. जयभास्कर द्वारा ताल वाद्य कचेरी का वादन, नाथूलाल सोलंकी द्वारा नगाड़ा वादन एवं महमूद फारुकी द्वारा दास्तानगोई दास्तान-ए-कर्ण की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होंगे।

इस अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में सोनल मानसिंह, गुलजार, एस.एल. भैरप्पा, चंद्रशेखर कंबार, किरण बेदी, लिंडा हेस, डेनियल नेगर्स, सुरजीत पातर, नमिता गोखले, कपिल कपूर, आरिफ मोहम्मद खान, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रघुवीर चौधरी, सितांशु यशशचन्द्र, विश्वास पाटिल, रंजीत होसकोटे, गीतांजलि श्री, सई परांजपे, दीप्ति नवल, मालाश्री लाल, सुदर्शन वशिष्ठ, प्रत्यूष गुलेरी, एस. आर. हरनोट, होशांग मर्चेंट, लीलाधर जगूड़ी, अरूण कमल, बलदेव भाई शर्मा, सतीश अलेकर एवं विष्णु दत्त राकेश सहित अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि यह उत्सव सभी साहित्य प्रेमियों के लिए हर दिन नि:शुल्क है। इस उत्सव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 1000 पुस्तकों को प्रदर्शित किया जाएगा और पांच भारतीय प्रकाशकों की पुस्तकें बिक्री के लिए भी उपलब्ध होंगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संत कबीर जयन्ती पर बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने संत कबीर जयन्ती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने संत कबीर को धार्मिक एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था तथा उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में संत कबीर को समस्त मानव जाति का पथ-प्रदर्शक बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज को समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण के लिए संत कबीर की शिक्षाओं का अनुसरण करने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति सबीना ने लांगजा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में भाग लिया

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति श्रीमति सबीना, कार्यवाहक मुख्य

न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय व कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला ने 10 मई, 2022 को लांगजा (किन्नौर) में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में भाग लिया। इस विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनजातीय क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों के बारे मे जागरूक करने के लिए किया गया। जिसमे लगभग 70 लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त उन्होने विलेज लीगल केयर एंड सुपोर्ट सेंटर लांगजा (किन्नौर) का भी दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने कब्बड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने खेलो इण्डिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश की पुरूष कब्बड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरूष कब्बड्डी टीम टीम ने फाइनल मैच में हरियाणा की टीम को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए टीम के सभी सदस्य, टीम कोच व मैनेजर सहित समस्त स्टाफ बधाई का पात्र है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवों के सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में 16 और 17 जून, 2022 को प्रस्तावित अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन के स्थल एचपीसीए स्टेडियम का दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन स्थल पर

विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर और परिधि गृह का भी दौरा किया।

इससे पहले, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) मैदान में मुख्यमंत्री के आगमन पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साई मैदान में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सप्ताह के दौरान ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री के साथ सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा और भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक कपूर भी उपस्थित थे।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने किया अभूतपूर्व विकास, कई मानकों में केरल को पीछे छोड़ा:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के पड्डल मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 20,000 मेधावी विद्यार्थियों के लिए

निःशुल्क लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस पर 83 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इस अवसर पर सभी मंत्रियों ने अपने जिलों से कार्यक्रम में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित किया। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षित नागरिक लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी देन है। विद्यार्थी सही कार्य के लिए तत्परता से आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के विचार शुद्ध और ईमानदार होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के विजेता विद्यार्थियों का यह वर्ग अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अगली बार लैपटॉप जीतने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई मानकों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हम सभी के गर्व का विषय है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले लड़कियों की शिक्षा को गम्भीरता से नहीं लिया जाता था, परन्तु वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में वे लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करना उनकी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लैपटॉप वितरण में कुछ विलम्ब हुआ, परन्तु अब प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के बदलाव से शिक्षा प्रणाली में भी बहुत परिवर्तन आया है और लैपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल जैसे आधुनिक उपकरण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बन गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मण्डी में नया राज्य विश्वविद्यालय खोला है जिससे मण्डी सहित निकटवर्ती जिलों के छात्रों को उनके घर-द्वार पर उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही पूर्ण रूप से क्रियाशील होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को जल्द ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वेतनमान प्रदान किया जायेगा।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों से भी संवाद किया। विद्यार्थियों ने लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनसे कड़ा परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने 'आजादी का अमृत महोत्सव' का सिग्नेचर सॉन्ग भी जारी किया। इस गीत की रचना एवं गायन डॉ. गोपाल कृष्ण, प्रो. सुरेंद्र शर्मा, डॉ. सतीश ठाकुर, डॉ. लाल चंद और डॉ. हेम राज द्वारा किया गया है।

इस अवसर पर राज्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों पर आधारित वृत्तचित्र 'शिक्षा के नए आयाम' का भी प्रदर्शन किया गया।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में राज्य के कुल बजट का लगभग 16 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा को अधिक भविष्योन्मुख बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लायी गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में मेधावी छात्रों के लिये राज्य सरकार ने अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए हर घर पाठशाला आरम्भ की गई। उन्होंने कहा कि गत साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश में अध्यापकों के 10 हजार से अधिक पद भरे गये हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50 वर्षों के अंतराल के बाद मंडी में एक और राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को जाता है।

इस अवसर पर मंडी जिला के लगभग 2900 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किये गये।

इस अवसर पर प्रधान सचिव, शिक्षा मनीष गर्ग ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक विनोद कुमार, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी व प्रकाश राणा, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य, नगर निगम मंडी की महापौर रूपाली जसवाल, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति डॉ. डी.डी. शर्मा, पूर्व विधायक डी.डी. ठाकुर व कन्हैया लाल, उपायुक्त मण्डी अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस-2022 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। राज्य में यह दिवस 120 प्रमुख स्थानों के अलावा 1200 ग्रामीण स्थलों पर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दृष्टिगत इस आयोजन के दौरान अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों से संबंधित जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों से अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को योग के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन स्थल या किसी झील के आसपास के स्थल चिन्हित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने योग के विभिन्न छायाचित्र भी साझा करने के लिए आग्रह किया है ताकि लोगों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

आयुष विभाग के निदेशक विनय सिंह ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाने के लिए जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। लोगों को योग के प्रति प्रेरित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर सचिव आयुष राजीव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के आयोजन के लिए समन्वय बैठक

शिमला/शैल। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति आम जन में जागरूकता लाने के लिए 26 जून, 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए समन्वय

बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

यह कार्यक्रम राज्य कर एवं आबकारी विभाग तथा हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

प्रधान सचिव ने अधिकारियों को कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि इसे अभियान की तरह आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर नशा निवारण विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता, मैराथन, नशे की रोकथाम के लिए शपथ, लघु नाटिका, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता प्रदर्शनी और अन्य कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सुभासीष पन्डा ने कहा कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से जिला स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां आपसी समन्वय से समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार ओम प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, प्रबन्धन सुशील कापटा, डीआईजी अरूल कुमार, निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल राजेश शर्मा, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सुनील शर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राहुल चौहान, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय पाठक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमीरपुर से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 195 नई बसों में से 16 बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों के लिए

आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निगम के लिए इन बसों की खरीद की गई है।

इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी बजट घोषणा के अनुरूप हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 205 नई बसें खरीदी जानी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 87 बसें पहले ही पहुंच चुकी हैं और शेष बसें शीघ्र ही राज्य में पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये बसें राज्य परिवहन के बेड़े की पुरानी और खराब हो चुकी बसों के स्थान पर संचालित होंगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़क परिवहन का मुख्य साधन है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और आरामदायक यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के बजट में उन्होंने 360 नई बसें शामिल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन सभी बसों को खरीद कर निगम को उपलब्ध कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी बसें बीएस-6 मानकों के अनुरूप होंगी और इनमें सीसीटीवी कैमरा, रियर व्यू कैमरा, वीएलटीडी ट्रैकिंग सिस्टम आदि नवीनतम सुविधाएं हैं।

इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने नई शामिल बसों के चालकों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी, विधायक नरेंद्र ठाकुर, राकेश जमवाल और अरुण कुमार मेहरा, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, कार्यकारी निदेशक भूपिंदर अत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता इसे बनाना पड़ता है जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

बढ़ता कर्ज विकास नहीं भविष्य को गिरवी रखना होता है

इस वर्ष के अन्त में प्रदेश में चुनाव होने हैं मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में जाकर नयी-नयी योजनाओं की घोषणायें कर रहे हैं। इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिये कितने करोड़ धन की आवश्यकता होगी। यदि इन आंकड़ों का आकलन किया जाये तो यह योग शायद कुल बजट से भी बढ़ जायेगा। यह धन जुटाने के लिये कर्ज के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं होगा। केंद्र हिमाचल को जयराम के कार्यकाल में कितना सहयोग दे चुका है और उसका व्यवहारिक सच क्या है इस पर पिछले अंक में चर्चा कर चुका हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वयं मुख्यमंत्री जो आंकड़े परोस चुके हैं उन्हीं से इस सहायता पर संदेह होता है। यह संदेह कैग कि 31 मार्च 2020 को समाप्त हुये वर्ष को लेकर आई रिपोर्ट से और पुख्ता हो जाता है। इस रिपोर्ट के दूसरे ही पन्ने पर वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के आंकड़े दर्ज हैं। तालिका 1-2 में गैर योजना गत अनुदान, राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान में वर्ष 2017-18, 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिये इन स्कीमों में शुन्य अनुदान दिखाया गया है। संभव है कि मुख्यमंत्री और विपक्ष तथा मीडिया के विद्वानों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन कैग रिपोर्ट में यह दर्ज है और यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है तथा सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है।

प्रदेश का कर्ज भार 70000 करोड से पार जा चुका है। पिछली सरकार 46000 करोड का कर्ज छोड़ कर गयी थी। इस सरकार को हर वर्ष करीब 5000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। ऐसे में जब अब की जा रही घोषणाओं पर होने वाले खर्च को इसमें जोड़ा जायेगा तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से एक लाख करोड़ तक पहुंच जायेगा। इसका अर्थ होगा कि अगले 5 वर्षो में यह कर्ज कई गुना बढ़ जायेगा। क्योंकि लिये हुए कर्ज की किस्तें और ब्याज चुकाने में ही सारे साधन लग जायेंगे। इसका दूसरा परिणाम होगा कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी में प्रदेश आज ही देश में छठे स्थान पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में स्थिति क्या हो जायेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आज ही सरकार राशन कार्डो के पुन: परीक्षण से सस्ते राशन के लाभार्थियों की संख्या कम करने का प्रयास कर रही है। जिस पर फिलहाल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मनरेगा में अभी तक नये वर्ष में बजट जारी नहीं हो सका है। हर विभाग में रिक्तियां चल रही है जिन्हें सरकार भरने में असमर्थ है। 2019 में स्कूलों में बच्चों को सरकार वर्दी नहीं दे पायी है। बल्कि अन्य वर्षो में भी वर्दी वितरण समय पर नहीं हो पाया है। सैकड़ों बच्चों को सिलाई के पैसे का भुगतान नहीं हो सका है। कैग रिपोर्ट में वर्दियों को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये हैं। ऐसे दर्जनों मामले कैग रिपोर्ट में ही दर्ज हैं जो सरकार की आर्थिक स्थिति का खुलासा सामने रखते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। सरकार बैंकों को निजी क्षेत्र को सौंपने के लिये हर समय प्रयासरत है। 2014 के मुकाबले सरकार का कर्ज भार दोगुना से भी अधिक हो चुका है। अधिकारी प्रधानमंत्री को आगाह कर चुके हैं कि यदि मुफ्ती की घोषणाओं पर रोक न लगायी गयी तो हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। ऐसी वस्तुस्थिति में केंद्र किसी भी प्रदेश की कोई बड़ी आर्थिक सहायता नहीं कर पायेगा यह तय है। सारी सहायता घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पायेंगी। इसलिए आज सत्ता के लिये प्रदेश को और कर्ज के गर्त में ले जाने के हर प्रयास से बचना होगा। मुख्यमंत्री को यह बताना होगा कि यह घोषणायें चुनावी वर्ष में ही क्यों हो रही है? इनके लिए धन का प्रावधान क्या है? यह स्पष्ट करना होगा कि इसके लिये और कर्ज नहीं लिया जायेगा। कर्ज लेकर खैरात बांटने की नीति से परहेज करना होगा।

भारत में नफरत कभी सफल नहीं होगी लेकिन दुश्मनों से सावधान रहना होगा

गौतम चौधरी

असहिष्णुता नफरत पैदा करती है और नफरत पूर्वाग्रह तथा बहिष्कार की ओर ले जाती है।

बिहार में एक मुस्लिम परिवार ने हाल ही में राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवालिया क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपये की अपनी संपत्ति देने की पेशकश की है, जो सहिष्णुता और स्वीकृति की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उक्त परिवार ने देश के बारे में चल रहे उन तमाम प्रकार के दुष्प्रचारों को आइना दिखा दिया है जो देश को बदनाम करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से चलाये जा रहे हैं। इस महान कार्य के लिये पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख, आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि श्री खान और उनके परिवार की भेंट दो अलग-अलग समूहों के बीच सामाजिक शांति, बंधुत्व और सद्भाव का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों की मदद के बिना इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना नामुमकिन है।

इससे पहले, बैंगलोर के एक अन्य मुस्लिम व्यवसायी ने मंदिर के निर्माण के लिए अपनी बहुमूल्य संपत्ति दान की थी। मुस्लिम व्यवसायी ने एक हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए बेंगलुरु के बाहरी इलाके में 1.5 गुंटा (लगभग 1634 वर्ग फुट) मूल्यवान संपत्ति दी इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर प्रशंसा प्राप्त हो रहा है। यही नहीं इस दान के बाद वे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। स्थानीय शहरी भी उनकी प्रशंसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। माल परिवहन सेवाओं के मालिक एचएमजी बाशा ने देखा कि होसकोटे तालुक के वलगेरापुरू में उनकी तीन एकड़ भूमि के टुकड़े के पास एक हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर बेहद छोटा है और दिन व दिन वहां भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। हनुमान मंदिर को व्यवस्थित करने में प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर ट्रस्ट मंदिर का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। बाशा ने मंदिर ट्रस्ट को भूमि दान कर दी। बाशी की जमीन बेहद मूल्यवान थी क्योंकि उसके पास से ही राजमार्ग गुजर रहा है। बाशा ने मूल्य का कोई हिसाब ही नहीं लगाया और कहा कि जब भगवान का काम हो रहा है तो उसमें मूल्य का क्या करना। बासी ने अपनी संपत्ति के बारे में बताया कि जिन्हें उन्होंने जीवन भर संजोया है, हिंदू और मुसलमान अनादि काल से एक साथ रहते आए हैं। आज, विभाजनकारी चीजों के बारे में बहुत बातें होती है। अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, हमें एक देश के रूप में एकजुट रहना है तो छोटी मोटी आकांक्षाओं को त्यागना होगा। तभी हमारा देश महान बनेगा और दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होगा।

ये दो-तीन घटनायें चूंकि बड़ी थी इसलिये इसे समाचार माध्यमों या फिर सोशल मीडिया में स्थान मिला लेकिन भारत में लगभग प्रति दिन इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिल जायेंगे। उसका प्रकाशन नहीं हो पाता है और उसे प्रचार भी नहीं मिल पाता है लेकिन समाज में इस प्रकार के लोग बड़ी संख्या में हैं, जो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और देश को एक बनाने की कोशिश में लगे हैं। सांप्रदायिक मैल और घृणा से मुद्र रखने में प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में नफरत का कोई स्थान नहीं है और कोई भी इस सामाजिक ताने-बाने जिसे सामंजस्यपूर्ण बनने में सदियों लग गये उसे अलग करने में सफल नहीं होगा।

सामान्य तौर पर, सामाजिक स्तर पर सामाजिक हस्तक्षेप और चेतना के माध्यम से ही नफरत की राजनीति को खत्म किया जा सकता है। हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो लगातार हिन्दू व मुसलमानों को एक करने में लगे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और एकता कायम करने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। यह एकता इतनी मजबूत है कि महज एक छोटे से राजनीतिक बयान से तोड़े नहीं जा सकते। हालांकि कुछ देश तोड़ने वाली शक्तियां लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि देश का मुसलमान असहज हो जाये लेकिन कुछ घटनाओं को छोड़ बड़े परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं दिखता है। सच पूछिये तो इस प्रकार के व्यक्तिगत कृत्यों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस तरह का दृष्टिकोण बढ़ती नफरत और वैमनस्य का प्रतिकार हो सकती है।

अभी हाल ही में कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने ऐसे ब्यान प्रस्तुत किये जिसके कारण एक खास वर्ग में अविश्वास उत्पन्न हुआ। उस अविश्वास को भुनाने के लिए हमारे खिलाफ दुनियाभर के दुश्मन आनन-फानन में सक्रिय हो गए। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया। दुबई में भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया कंपेन चलाया गया लेकिन भारत सरकार इस मामले में सजगता दिखाते हुए ऐसी कार्रवाई की, जिसे करने के लिए पाकिस्तान या फिर अन्य इस्लामिक देशों को लाख बार सोचना पड़ेगा। भारत का समाज बेहद सहिष्णु समाज है। इस समाज में असहिष्णुता का कहीं कोई स्थान नहीं है। डेढ़ अरब की आवादी वाले भारत में प्रति दिन कोई न कोई घटनाएं घटती रहती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि विभाजनकारी घटनायें नहीं घटती है लेकिन इससे ज्यादा सकारात्मक और एक-दूसरे को सहयोग करने वाली भी घटनायें घट रही है। पश्चिमी मीडिया या फिर हमारे दुश्मन उन घटनाओं का ज्यादा प्रचार करते हैं, जो विभाजनकारी है। इसलिए हमें भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ हो रहे षडयंत्रों से सावधान रहना होगा।

कौशल विकास में मंडी जिले को एक्सिलेंस अवार्ड

शिमला। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने मंडी जिले को डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2020-21 के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सिलेंस' अवार्ड से नवाजा है। मंडी को जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस अवार्ड के लिए पूरे देश के चुने गए श्रेष्ठ 30 जिलों में हिमाचल से केवल मंडी जिले का नाम चयनित हुआ था।

जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने दल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने यह अवार्ड सौंपा। इस समारोह में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी उपस्थित थे।

उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के दिशानिर्देशों के अनुरूप जिले में अभिनव योजना के माध्यम से कौशल विकास परितंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया है। युवाओं के कौशल उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की जमीनी स्तर पर कौशल विकास कार्यो को और गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दी भारत की नियति

– अनुराग सिंह ठाकुर –
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण
तथा खेल एवं युवा कार्य मंत्री

राजनीति में सात दिन एक लंबा समय हो सकता है, लेकिन किसी देश के इतिहास में आठ साल का समय बहुत कम होता है। फिर भी, इस कम समय में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की वैश्विक प्रोफाइल को बड़े पैमाने पर ऊपर उठाया है और विश्वगुरु के रूप में राष्ट्र के खोये हुये गौरव, प्रतिष्ठा और गरिमा को बहाल किया है। जैसा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व के नौवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, भारत न केवल घरेलू मोर्चे पर बल्कि दुनिया में भी आगे बढ़ेगा। भारत की नियति का मार्ग दृढ़ता से निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय हित को पारंपरिक भू-राजनीति से ऊपर रखने की प्रधानमंत्री श्री मोदी की 'इंडिया फर्स्ट' नीति ने निस्संदेह विदेशों में भारत के उदय को प्रेरित किया है। हार्ड और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का एक निपुण संयोजन, प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता के एक मजबूत प्रदर्शन के साथ युग्मित है और इनका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करेगा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के दौरान हम कोई मौका नहीं गवाएंगे और इसने 'इंडिया फर्स्ट' नीति में जान डाल दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा भारत की सभ्यतागत विरासत और इसकी संस्कृति को बेरोक-टोक बढ़ावा दिये जाने से इसे ताकत मिली है।

पिछली सरकारों ने भारत की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन प्रयासों का सीमित प्रभाव पड़ा। पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किये बिना पर्यटन को बढ़ावा देना, या भारत की बहु-रंगी अपील को केवल एक स्मारक तक सीमित करना, या इससे भी बदतर, लोकप्रिय संस्कृति के सबसे निचले हिस्से को भारत की विरासत के रूप में प्रदर्शित करना, इन सब ने सॉफ्ट पावर के मोर्चे पर भारत के उदय को रोक दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव लाये हैं, कैनवास को बड़ा किया है और पूरक तत्वों को शामिल किया है। उदाहरण के लिए, इस प्राचीन भूमि से दुनिया को एक उपहार के रूप में योग अब दुनिया भर में एक घरेलू नाम है, संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करने और भारत की इस अनूठी सभ्यतागत विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिये कई पहलों के साथ इसका समर्थन करने की पहल के लिए धन्यवाद।

अतीत में,'वसुधैव कुटुम्बकम' एक खाली नारा बन गया था, एक क्लिच जो अपने मजबूत नैतिक अर्थ को खो चुका था। 'विश्व एक परिवार है' कहना और भारत के सभ्यतागत लोकाचार में निहित इस शाश्वत सत्य को जीना दो अलग-अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिखा दिया है कि भारत न केवल अपने प्राचीन संतों के ज्ञान और अपने प्राचीन ग्रंथों में निहित इस कहावत में विश्वास करता है, बल्कि इसे जीता भी है। इसलिए, जब विकसित दुनिया ने कोविड-19 वैक्सीन के साथ दूसरों की मदद करने में अनिच्छा दिखाई, तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पड़ोसियों के साथ-साथ दूर के देशों की भी मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। हाल के दिनों में कई मायनों में, 'वैक्सीन मैत्री' भारत का सबसे बेहतरीन क्षण था जब हमने दुनिया को दिखाया कि हम एक राष्ट्र और एक सभ्यता के रूप में अलग हैं 'कि हम विकसित दुनिया के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि हमें भी प्रतिकूल स्थितियों का लाभ लेना चाहिए'।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिये 'वसुधैव कुटुम्बकम', केवल महामारी सहायता को लेकर ही नहीं है। भारत पहला देश था जिसने आपदा राहत के साथ संपर्क किया जब नेपाल में एक भयानक भूकंप आया, इसके बाद ही इस क्षेत्र के अन्य देशों ने इस संबंध में कारवाई की। ऐसे समय में जब श्रीलंका अशांत समय से गुजर रहा है, भारत ने संकट से निपटने में मदद के लिए बेझिझक कदम बढ़ाया है। काबुल के पतन और तालिबान के उदय के बाद दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह फेर लिया है। इस महत्वपूर्ण घटना के सुरक्षा निहितार्थों के बावजूद, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को खाद्य राहत प्रदान करना चुना है। अतीत में, यह भारत ही था जिसने अफगानों को एक संसद भवन उपहार में दिया था और अफगानिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बांधों में से एक का निर्माण किया था।

'वसुधैव कुटुम्बकुम' के उदात्त सिद्धांत को जीने वाले, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं और उससे जुड़ते हैं, उसमें मूल्यों को बहाल करने की भारत की सूची उतनी ही लंबी है, जितना कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण व्यापक है। उदाहरण के लिए, मजबूर घरेलू कारणों से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाते हुए भी, भारत ने यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों को गेहूं की जरूरत है, उन्हें मामला-दर-मामला आधार पर गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय के पीछे यह गहरा नैतिक विचार है कि यदि विश्व एक परिवार है तो खाद्य सुरक्षा अकेले भारत के लिये नहीं हो सकती। जबकि अन्य विश्व नेता मूल्यों और सिद्धांतों के लिए लिप सर्विस करते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ऐसे मूल्यों और सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हैं जो दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव का मार्गदर्शन करते हैं।

'डिजिटल इंडिया' की कहानी इतनी चर्चित है कि फिर से बताने की जरूरत नहीं । अब हम तीसरी सबसे बड़ी संख्या में स्टार्टअप की मेजबानी करते हैं और 100 यूनिकॉर्न का दावा करते हैं। हमारे पास बेहतरीन यूपीआई में से एक है जिसने डिजिटल भुगतान को अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय बना दिया है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का प्रबंधन और निगरानी डिजिटल रूप से की गई। डिजिटल समावेशन प्रधानमंत्री श्री मोदी की 'डिजिटल इंडिया' नीति की आधारशिला रहा है। दूसरे देशों के विपरीत, हम प्रौद्योगिकी साझा करने के इच्छुक हैं। जलवायु पर, भारत ने अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, सशक्त विकास और हरित निवेश के मार्ग का नेतृत्व किया है, जो अनिच्छुक लोगों के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है।

हम जो यह अभूतपूर्व उत्साह देखते हैं, भारतीयों में विश्वास है कि वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री श्री मोदी का मानना है कि यह किया जा सकता है, यह सब व्यापक है। हमारे खिलाड़ी, 'यंग इंडिया' के बेहतरीन उदाहरणों में से और 'कैन डू' मोदी मंत्र से प्रेरित हैं, उत्कृष्ट हैं और घरेलू ट्राफियां ला रहे हैं जिनका हम पहले केवल सपना देख सकते थे। बॉलीवुड अब केवल एक निश्चित किस्म की लोकप्रिय संस्कृति के बारे में नहीं है। हमारे बेहद प्रतिभाशाली फिल्म उद्योग ने विश्व स्तर की विषय-सामग्री का निर्माण करने के लिए रचनात्मकता, संस्कृति और प्रौद्योगिकी को संयोजित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है जो विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मनोरंजन मीडिया और प्रौद्योगिकी ने भारत को एक विषय-सामग्री उप-महाद्वीप बनाने के लिए मूल रूप से विलय कर दिया है, जो दुनिया भर में सामग्री उत्पादकों के लिए एक आदर्श मंच है। भारत विषय-सामग्री का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में, भारत को कान्स में इस साल के 'कंट्री ऑफ ऑनर' के रूप में नामित किया गया है।

भारत की विशालता-और इस महान राष्ट्र के बारे में दुनिया को अभी तक क्या पता चला है-इसका उदाहरण प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा विश्व के नेताओं के लिए दिये गये उपहारों से है। कोई भी दो उपहार एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो उपहार एक ही जगह से नहीं आते। प्रत्येक अद्वितीय है, प्रत्येक अपने सच्चे अर्थों में भारत की सॉफ्ट पावर के महान मोज़ेक के एक छोटे से टुकड़े का प्रतीक है, प्रत्येक एक सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में भारत की ऊंचाइयों और उपलब्धियों की महानता का जश्न मनाता है। भारत आज मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेज सकता है, भारत सुपरसोनिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, भारत बेहतरीन रचनात्मक चिंतन पैदा कर सकता है, भारत बुनियादी ढांचे की कमी को तेजी से पूरा कर सकता है, भारत अन्य देशों की तुलना में एक महामारी का बेहतर प्रबंधन कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देशों की तुलना में तेजी से पुन: आगे बढ़ा सकता है, भारत गरीबी और असमानता को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, और, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा हो सकता है।

जैसा कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह माना जाना चाहिए कि इन आठ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आने वाले दशकों के लिए भारत के बेरोक-टोक उत्थान की नींव रखी है। भारत अपने घरेलू मोर्चे पर खुद समृद्ध होता रहेगा और राष्ट्रों के समूह में भारत का कद बढ़ता रहेगा। एक प्राचीन सभ्यता के रूप में आज की दुनिया में अपना सही स्थान पा रहा है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्वीकार किया जायेगा-एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र जो नेतृत्व और प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सचमुच और निसंदेह भारत की नियति को बदल दिया है।

प्राकृतिक खेती अपनाकर खुशहाल हो रहे सिरमौर जिला के किसान व बागवान

शिमला। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वाकांक्षी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना प्रदेश के किसानों-बागवानों की आर्थिकी को संबल प्रदान कर रही है। खेती की इस तकनीक को अपनाने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ लागत मूल्य में भी कमी आती है।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को अपना कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ जिला सिरमौर के किसान भी खुशहाली के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं।

सिरमौर जिला में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, आत्मा द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षो में 411 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके अर्न्तगत 16 हजार 133 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 10 हजार 324 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। जिला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत एक हजार 29 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर पर 2 से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों के लिए कृषक भ्रमण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, ताकि किसान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्राकृतिक खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

प्राकृतिक खेती द्रव्य उत्पादन के लिए प्लास्टिक ड्रम पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपये प्रति ड्रम की दर से 3 ड्रम खरीदने पर अनुदान दिया जाता है। इसी तरह, गौशाला के फर्श निर्माण के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। देसी गाय की खरीद पर सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थी नाहन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कमलाहड के गांव खैरी चागण निवासी विशाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत तथा प्राकृतिक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों के समय की बचत होती है और उनकी जमीन बंजर होने से भी बचती है।

ग्राम पंचायत कमलाहड़ के गांव काटाफलाह के लाभार्थी चमन पुण्डीर ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षो से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और मुख्य फसल के साथ सह फसल भी उगाते हैं जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 46 करोड़ 15 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा इससे 1 लाख 54 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसके तहत अब तक 9 हजार 192 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है।

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस वर्ष के दौरान 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक कृषि का एक-एक मॉडल भी विकसित किया जाएगा, जिससे आस-पास के किसानों को प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में कम से कम 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में परिवर्तित करने तथा प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पंजकृत कर उनमें से श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई तकनीक के विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका अहम

शिमला/शैल। केन्द्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने डॉ.यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चदेल और विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारियों के साथ बातचीत की और विवि द्वारा शिक्षण, विस्तार और अनुसंधान के क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली।

गुर्जर ने फल विज्ञान विभाग में अल्ट्रा हाई डेंसिटी सेब के बगीचों का भी दौरा किया जहां उन्हें सेब की विभिन्न किस्मों, प्रशिक्षण और छंटाई के साथ-साथ उत्पादन, और उपज की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। प्रोफेसर चदेल ने बताया कि विश्वविद्यालय ने उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण मॉडल के तहत सेब के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार की है । उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय पहले से ही इस प्रणाली के तहत 42 मीट्रिक टन उत्पादकता हासिल कर चुका है जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में कई गुना अधिक है।

गुर्जर ने फ्लोरल क्राफ्ट लैब का भी दौरा किया जहां उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न उत्पादों की सराहना की। उन्होंने देशी जंगली फूलों और कृषि कचरे के मूल्यवर्धन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने विभिन्न हर्बल रंगों और उत्पादों को तैयार करने का कार्य कर रहे छात्रों के साथ भी बातचीत की। गुर्जर ने औषधीय और सुगंधित पौधों पर विश्वविद्यालय के कृषि ऊष्मायन केंद्र की प्रशंसा की, जो न केवल किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा था बल्कि औषधीय और सुगंधित पौधों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए भी सेवाएं प्रदान कर रहा था। नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुये गुर्जर ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा नई कृषि प्रौद्योगिकी पर शोध किसानों की आय में वृद्धि करके कृषक समुदाय के लिए फायदेमंद साबित होगा। एक ही भूमि से विभिन्न फलों और सब्जियों में अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न शोध कार्यो का किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिसके नवीनतम कृषि तकनीक और ज्ञान किसानों तक पहुंचता है। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के नचेर पार्क में एक देवदार का पेड़ भी लगाया।

प्रदेश में भाजपा अब चंद दिनों की मेहमान:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लोग भाजपा के कुशासन,

बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से बहुत दुखी हो चुके है और इसे सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना चुके है। उन्होंने कहा कि अभी हॉल ही में वह किन्नौर, रामपुर,आनी ब्लॉकों का दौरा कर के लोटी है। लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि रामपुर में महिला सशक्तिकरण समारोह में महिलाओं की भारी भीड़ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में भाजपा अब चंद दिनों की मेहमान है। महिलाओं ने पूरी तरह ठान लिया है कि वह भाजपा को सत्ता से बाहर करके ही रहेगी।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में इन दोनों भाजपा लोगों को लुभाने का असफल प्रयास कर रही है। साढ़े चार साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने लोगों की कोई सुध नही ली। अब चुनाव नजदीक आते देख भाजपा घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, जबकि सरकारी खजाना खाली पड़ा है। भाजपा अपनी राजनीतिक रैलियों के लिए सरकारी मशनरी व धन का खुल कर दुरपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह कहना कि अब सत्ता परिवर्तन की रिवायत बदेलगी और उनकी पुनः सत्ता वापसी होगी, मुगेरीलाल के हसीन सपने देख रही है। यह उनका चुनावों में हार की बोखलावट साफ दर्शता है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा शिमला नगर निगम चुनावों में अपनी हार के डर से भी सहमी हुई है। उन्होंने कहा कि यही बजह है कि वह इन चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने से कतरा रही है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह कांगड़ा, हमीरपुर, नाहन और सोलन जिलों के दौरे पर जाएगी, जहां वह जिला कांग्रेस कमेटियों की आम सभा की बैठकों मे शिरकत करेगी।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रही है जबकि भाजपा मुद्दों से भाग रही है।

एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्ष 2021 के लिये पीएसयू अवार्ड से सम्मानित

शिमला/शैल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) ने एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नन्द लाल शर्मा को वर्ष 2021 का पीएसयू अवार्ड प्रदान किया है। यह अवार्ड शर्मा द्वारा एसजेवीएन को वर्ष 2021 की सबसे कुशल और लाभदायक मिनी रत्न कंपनी बनाने में किये गये उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

नन्द लाल शर्मा शेडयूल-ए, मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमुख हैं। शर्मा ने संगठन के मौजूदा बिजनेस मॉडल को पुनर्गठित किया है, इसने एकल राज्य में एकल परियोजना संगठन के रूप में आरंभ कर इसका वर्तमान में लगभग 31500 मेगावाट का कुल पोर्टफोलियो एवं विकास के विभिन्न चरणों के तहत 50 से अधिक परियोजनाएं हैं। नन्द लाल शर्मा के गतिशील नेतृत्व में, एसजेवीएन वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, वर्ष 2030 तक 25000 मेगावाट तथा वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट स्थापित क्षमता के साझा विजन साथ विद्युत के विभिन्न स्रोतों के दोहन में तीव्रता से प्रगति कर रहा है।

शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में एसजेवीएन ने आगामी पांच वर्षो में 75000 करोड़ रुपए और आगामी दस वर्षो में 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जो देश के विकास की प्रगति तथा रोजगार सृजन, बुनियादीगत ढांचा विकास एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

एसजेवीएन ने वर्ष 1988 में 1500 मेगावाट की एकल जलविद्युत परियोजना के साथ शुरुआत की थी। आज, कंपनी ने भारत के आठ राज्यों और पड़ोसी देशों नेपाल एवं भूटान में उपस्थिति दर्ज की है। एसजेवीएन के पास अब जलविद्युत, ताप, पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएं, पावर ट्रांसमिशन और पावर ट्रेडिंग का विविध पोर्टफोलियो है। कंपनी ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक एक अधीनस्थ कंपनी का गठन किया है। वर्ष 1986 में स्थापित, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) भारत की नंबर 1 इक्विटी अनुसंधान और पूंजीगत निवेश पत्रिका है जो अपने पाठक-निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

विक्रमादित्य सिंह ने पिपली धार पंचायत के लिये 12,50 लाख रुपये स्वीकृत किये

शिमला/शैल। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास उनकी प्रमुखता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में यहां इस क्षेत्र में जो विकास कार्य शुरू किए थे उनको पूरा करना और उन्हें आगे बढ़ना उनका लक्ष्य है।

पिपली धार पंचायत की प्रधान सुनीता शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास में उनकी चिंता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रेम और विकास कि विरासत को जिस प्रकार विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ा रहें है वह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है।

पिपली धार पंचायत में विधायक आपके द्वार में लोगों को सम्बोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र ने उन्हें जो मान सम्मान दिया है उसके लिए वह सदैव उनके आभारी रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण का यह क्षेत्र विकास के मामलें में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि इस सब का श्रेय क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों को जाता है जो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते है।

विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि अब प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने है इसलिए उन्हें उनके हाथों को ओर मजबूत करना है जिससे यह क्षेत्र प्रगति के पथ पट निरंतर आगे बढ़ता रहें।

इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिये कुछ मांगे भी रखी जिसके लिए विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस दौरान पिपली धार पंचायत के विभिन्न कार्यो के लिये विधायक निधि से 12,50 लाख रुपये भी स्वीकृत किये।

इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक सोहन लाल, जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा,ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष चंद्र शेखर शर्मा, एमडी शर्मा प्रधान लाजवंती, पूनम ठाकुर, मीरा शर्मा, ऊषा, दवेंद्र, बीडीसी सीता शर्मा, रीता भारद्वाज, आशा वर्मा, प्रेम शर्मा, किरण सहित कई अन्य पार्टी पदाधिकारी, महिला मंडल, पंचायत के वार्ड सदस्य के अतिरिक्त कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे।

शैक्षणिक संस्थानों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के मध्य ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन

शिमला/शैल। सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों,

50 महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी (आईजीआरयूए) के साथ भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने और उन्हें ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा, उनका उपयोग कर सशक्त बनाने के लिए ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विकास पाठयक्रम चलाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा डॉ. रजनीश की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ड्रोन नीति-2022 के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य में ड्रोन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस नीति को 06 जून, 2022 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह ड्रोन संबंधित विभिन्न पाठयक्रमों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त श्रम शक्ति और कौशल विकास के सृजन में सहयोग करेगा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अन्तर्गत अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के साथ ड्रोन से संबंधित पाठयक्रमों को जोड़ने से छात्रों को ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए

शिमला/शैल। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित छठे दीक्षांत समारोह के दौरान एक गरिमापूर्ण समारोह में दस मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किये।

राष्ट्रपति ने इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर स्वर्ण पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि छात्र जीवन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो हमारे व्यक्तित्व के समग्र विकास और हमारी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। हिमाचल प्रदेश ने एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े राज्यों को रास्ता दिखाया है और जिसका श्रेय इस पहाड़ी राज्य के शिक्षकों को जाता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों और छात्रों की सुविधा के लिए शीघ्र ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना परिसर होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का ध्येय स्वरोजगार और नवीन शिक्षा प्रदान करना रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 400 से अधिक छात्र पदक और डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि इन वर्षों में विश्वविद्यालय ने प्रगति की है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए, इससे जिम्मेदारी की भावना आती है, जो समाज में ज्ञान और एकता का मार्ग प्रशस्त करती है और एक मजबूत और श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अभूतपूर्व विकास का, जो श्रेय हासिल किया है, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि देश प्रगति और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ विश्व नेता के रूप में उभरे हैं, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सीखने की प्रवृत्ति और इच्छा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यह कभी न खत्म होने वाली और सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में सफलतापूर्वक शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पात्र आबादी के शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में भी देश में अग्रणी राज्य रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेधावी छात्रों को पीएचडी उपाधियां प्रदान कीं।

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस. पी. बंसल ने राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शोध पर विशेष ध्यान देते हुए छात्रों को रोजगारन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को करेगी साकार:साधवी निरंजन

शिमला/शैल। केंद्रीय राज्य खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण विकास मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूर्ण करेगी। गत आठ वर्षों के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने अनेकों कार्यक्रम तथा कल्याणकारी योजनाओं आरंभ की हैं जिससे गरीबों तथा पात्र लोगों की जीवन यापन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित हो रही है।

धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय

के सभागार में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि केंद्रीय राज्य खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण विकास मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्य द्वारा आरंभ की गई योजनाओं से लोगों के आवास, पेयजल की उपलब्धता, भोजन, स्वास्थ्य तथा पोषण, जीवनयापन तथा वित्तीय समावेश में बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि गत वर्षों में विकास की दुगुनी रफ्तार हुई है, कोरोना की महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी आम जनमानस की सुरक्षा के लिए वैक्सीन से लेकर राशन तक की उपलब्धा करवाया गया इसी के साथ निर्धान लोगों को रोजगार की दि ा में आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकारों की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने पीएम फंड फार चिल्ड्रन की शुरूआत भी की गई है जिसमें कोविड काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के शिक्षा इत्यादि के लिए मदद मुहैया करवाई गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), जल जीवन मिशन एवं अमृत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हैल्थ एण्ड वैलनेस सैन्टर तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाएं आम जनमानस के लिए काफी कारगर साबित हो रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित किया तथा योजनाओं को लेकर फीडबैक भी ली। इससे पहले उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिला में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार आरके मीणा, उप सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यशपाल, सौरभ अग्रवाल, अतिरिक्त निजी सचिव, एडीसी गंधर्वा राठौढ, ग्रामीण विकास विभाग के सह निदेशक राबिन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के द्वितीय सत्रको संबोधित किया

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने

कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्यपाल ने कहा, देश का भविष्य और दिशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करेगी।

उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रत्येक छात्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे डिग्री लेकर समाज से जुड़ने वाले है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और डिग्री धारक आज से नए अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करके हमें केवल नौकरी चाहने वाला नहीं बनना है, बल्कि डिग्री को रोजगार प्रदाता बनने के लिए भी उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि समाज की समस्याओं को समझना और उनसे कैसे निपटना है, यह समझना जरूरी है, जिसके लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं की पहचान उस संस्थान से की जाएगी, जहां से उन्होंने आपकी शिक्षा प्राप्त की है।

राज्यपाल ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में देश का भविष्य तय होगा। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के विचारों पर निर्भर करेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी हमें अमृत काल देने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उसे समझना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरन्तर उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्री प्रदान की।

इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता के अलावा छात्रों के जीवन में रचनात्मक मूल्यों का संचार भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए यह खुशी के पल हैं कि भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर यहां पधारे हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं लेकिन उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होना होगा।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। उन्होंने छात्रों से अगले 25 वर्षों के दौरान अमृत काल में राष्ट्र के लिए योगदान करने का आहवान करते हुए कहा कि हमारा देश एक युवा राष्ट्र है, जो हमारी ताकत है।

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. एच. एस.बेदी कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, अधिष्ठाता अध्ययन, परीक्षा नियंत्रक, विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर एवं छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

महंगाई की और पड़ेगी मार आरबीआई के रेपो रेट में इजाफा:राजेंद्र राणा

शिमला/शैल। पहले से महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार की मार झेल रही जनता पर अब महंगाई के नए प्रहार का मसौदा मोदी सरकार द्वारा तैयार किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50 फीसदी का इजाफा किया है। जो कि अब बढ़कर 4.90 फीसदी हो गया है। आरबीआई के मुताबिक 2022-23 में एक बार महंगाई फिर और बढने वाली है। वहीं, महंगाई का रिटेल इन्फ्लेशन भी 6.7 फीसदी रहेगा। यह बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। राणा ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियां आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ लाद रही हैं जो कि अब आम जनता की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। महंगाई की मार से बिलबिला रही जनता के लिए अब होम, ऑटो, पर्सनल लोन की ईएमआई अब और महंगी होगी। उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है कि बीजेपी के तानाशाह दौर में मध्यमवर्गीय और नौकरी पेशा लोग कहां जायें, क्या करें व अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करें? राणा ने कहा कि प्रचंड बहुमत लेने के बाद बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ लगातार दगा कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र में जनता से बफादारी की बजाय अदाकारी व कलाकारी से सिर्फ सत्ता हासिल करने के मंसूबे बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी देश और प्रदेश की जनता को लग रहा है कि आगे चलकर महंगाई कम हो जाएगी तो जनता इस मुगालते पर गलतफहमी में न रहे और आने वाले समय में महंगाई के नए प्रहार के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दूसरा नाम अब महंगाई बन चुका है। कांग्रेस कार्यकाल में 70 वर्षों की सतत मेहनत के बाद अर्जित व खड़ी की गई देश की संपत्तियां व परि-संपत्तियां बिक चुकी हैं। ऐसे में देश लगातार पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार के दम पर सत्ता हासिल करने पर है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सिरमौर कार्यकर्ताओं के पत्र से कांग्रेस की एकजुटता पर उठे सवाल

शिमला/शैल। प्रदेश विधानसभा के चुनाव सितम्बर – अक्तूबर में होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। वैसे तो हिमाचल में हर पांच वर्ष बाद सत्ता बदलती आयी है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह से लेकर शान्ता, धूमल तक कोई भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। बल्कि शान्ता और धूमल तो विधानसभा चुनाव तक भी हार चुके हैं। इन दोनों का शासन तो जयराम के शासन से हजार दर्जे बेहतर रहा है। इस नाते जयराम और उनकी सरकार का हारना तय माना जा रहा है। लेकिन इस बार प्रदेश के राजनीतिक वातावरण में वीरभद्र सिंह की मृत्यु और आप के चुनाव लड़ने के ऐलान से भारी बदलाव आया है। पंजाब में आप की अप्रत्याशित जीत से हिमाचल की राजनीति भी प्रभावित हुई है। प्रदेश में दो बार केजरीवाल भगवंत मान के साथ और मनीष सिसोदिया अकेले यहां आ चुके हैं। इन यात्राओं से आप के नेतृत्व ने शिक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाये जाने का सफल प्रयास भी कर दिया है। इस प्रयास से आप आज हिमाचल में 2.5 से 3% तक वोट ले जाने तक पहुंच चुकी है। इस प्रतिशत से यह माना जा रहा है कि आप अपने तौर पर शायद कोई सीट न जीत पाये लेकिन इससे कांग्रेस का नुकसान अवश्य कर देगी। आप को भाजपा का नुकसान करने और स्वयं सीट जीतने के लिये कम से कम 10% वोट तक पहुंचना होगा। भाजपा का प्रयास यही रहेगा कि आप 2.5% से 3% तक ही रहें। आप के प्रभावी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इस राणनीति का हिस्सा मानी जा रही है और ऐसा लगता है कि प्रदेश के चुनाव तक जैन को जेल से बाहर भी नहीं आने दिया जायेगा। आप की नयी कार्यकारिणी के गठन और हमीरपुर में केजरीवाल के शिक्षा संवाद के बाद भी सरकार की उस पर कोई प्रतिक्रिया न आना इसी दिशा के संकेत माने जा रहे हैं। इस वस्तुस्थिति में प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश में चल रही है उससे यह नहीं लगता कि वह इस बारे में सचेत भी है। क्योंकि प्रतिभा सिंह की मंडी में जीत का एक बड़ा कारण स्व. वीरभद्र सिंह के प्रति उपजी सहानुभूति भी रही है। इसी सहानुभूति के चलते प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनी है। लेकिन उनकी अध्यक्षता पर उसी समय प्रश्नचिन्ह भी लग गये हैं जब उनके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिये गये। जबकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रयोग अन्य राज्यों में सफल नहीं रहा है। कार्यकारी अध्यक्षों के साथ ही अन्य बड़े नेताओं मुकेश, सुक्खु, आशा, आनन्द शर्मा, कॉल सिंह आदि के लिये भी पदों का प्रबंध किया गया। इसमें मुकेश ही अकेले ऐसे नेता है जो पहले से ही नेता प्रतिपक्ष थे। जब नेताओं को इस तरह से समायोजित किया गया तब कार्यकर्ताओं और क्षेत्रों का भी ख्याल रखना पड़ा और लंबी चौड़ी कार्यकारिणी बनानी पड़ गयी। इसमें जिला शिमला से सबसे ज्यादा लोगों को कार्यकारिणी में जगह देनी पड़ गयी। यह जगह देने से अन्य जिलों के साथ संतुलन गड़बड़ा गया है। दूसरी ओर यदि इस कार्यकारिणी के बाद पार्टी की कारगुजारी पर नजर डाली जाये तो अभी तक पुलिस पेपर लीक के मामले से हटकर कोई और बड़ा मुद्दा पार्टी जनता के सामने नहीं रख पायी है। इसमें भी दावे के बावजूद ऑडियो टेप जारी नहीं किया गया है। पेपर लीक मामला सीबीआई तक क्यों नहीं पहुंचा है इसको लेकर सुक्खू ने जब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा तब उनके साथ सारे बड़े नेता क्यों नहीं थे। इसका कोई जवाब नहीं आया है। अब प्रतिभा सिंह के दौरों में भी बड़े नेताओं का एक साथ न रहना सवालों में है। प्रतिभा सिंह की सभाओं में कम हाजिरी भी अब चर्चा में आने लग गयी है। सिरमौर में तो कुंवर अजय बहादुर सिंह के खिलाफ जिला नेताओं का पत्र तक आ गया है। हर्षवर्धन चौहान कैसे और क्यों मंच की बजाय कार्यकर्ताओं के बीच बैठे यह एक अलग सवाल बन गया है। कुल मिलाकर सभी बड़े नेता अपनी – अपनी सीट निकालने तक सीमित होते जा रहे हैं। अपने – अपने जिले की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पूर्व मंत्री मनकोटिया ने तो खुलकर वंशवाद हावी होने का आरोप तक लगा दिया है। यहां तक कहा जा रहा है कि 42 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार मैदान में होंगे जिनके परिवारों से कोई न कोई विधायक सांसद या मंत्री रहा है। यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि नेतृत्व अभी तक सरकार के खिलाफ ऐसा कोई मुद्दा नहीं ला पाया है जिस पर सरकार घिर जाती और जवाब देने पर आना पड़ता तथा कार्यकर्ता भी उस पर एकजुट होकर आक्रामक हो जाते।

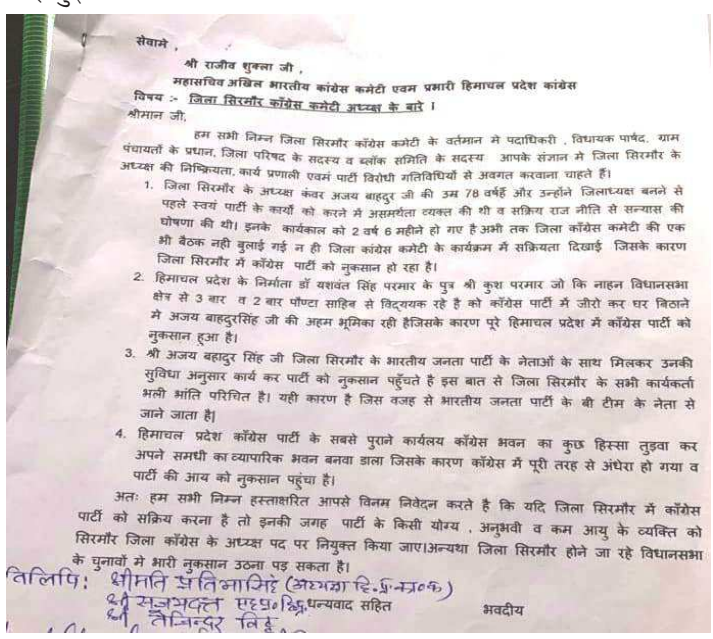

सेवामे,
श्री राजीव शुक्ला जी,
महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवम प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस
विषय :- जिला सिरमौर कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष के बारे ।
श्रीमान जी,
हम सभी निम्न जिला सिरमौर कॉंग्रेस कमेटी के वर्तमान मे पदाधिकारी , विधायक पार्षद, ग्राम पंचायतों के प्रधान, जिला परिषद के सदस्य व ब्लॉक समिति के सदस्य आपके संज्ञान मे जिला सिरमौर के अध्यक्ष की निष्क्रियता, कार्य प्रणाली एवम पार्टी विरोधी गतिविधियों से अवगत करवाना चाहते हैं।
1. जिला सिरमौर के अध्यक्ष कंवर अजय बाहदुर जी की उम्र 78 वर्षहैं और उन्होंने जिलाध्यक्ष बनने से पहले स्वयं पार्टी के कार्यों को करने मे असमर्थता व्यक्त की थी व सक्रिय राज नीति से सन्यास की घोषणा की थी। इनके कार्यकाल को 2 वर्ष 6 महीने हो गए हैं अभी तक जिला कॉंग्रेस कमेटी की एक भी बैठक नही बुलाई गई न ही जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में सक्रियता दिखाई जिसके कारण जिला सिरमौर में कॉंग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है।
2. हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ यशवंत सिंह परमार के पुत्र श्री कुश परमार जो कि नाहन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार व 2 बार पाँण्टा साहिब से विद्युयक रहे हैं को कॉंग्रेस पार्टी में जोरो कर घर बिठाने मे अजय बाहदुरसिंह जी की अहम भूमिका रही हैजिसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है।
3. श्री अजय बहादुर सिंह जी जिला सिरमौर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर उनकी सुविधा अनुसार कार्य कर पार्टी को नुकसान पहुँचते है इस बात से जिला सिरमौर के सभी कार्यकर्ता भली भाँति परिचित है। यही कारण है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के नेता से जाने जाता है।
4. हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी के सबसे पुराने कार्यलय कॉंग्रेस भवन का कुछ हिस्सा तुड़वा कर अपने समधी का व्यापारिक भवन बनवा डाला जिसके कारण कॉंग्रेस में पूरी तरह से अंधेरा हो गया व पार्टी की आय को नुकसान पहुंचा है।
अतः हम सभी निम्न हस्ताक्षरित आपसे विनम निवेदन करते है कि यदि जिला सिरमौर में कॉंग्रेस पार्टी को सक्रिय करना है तो इनकी जगह पार्टी के किसी योग्य , अनुभवी व कम आयु के व्यक्ति को सिरमौर जिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाए।अन्यथा जिला सिरमौर होने जा रहे विधानसभा के चुनावों मे भारी नुकसान उठना पड़ सकता है।
धन्यवाद सहित
भवदीय

क्या आप की इतनी बड़ी कार्यकारिणी अपेक्षाओं पर खरा उतर पायेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में आप की इकाई की कार्यकारिणी का अंततः गठन हो गया है। यह गठन पूर्व इकाई को भंग करके किया गया है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि जो नेता पहले से प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी निभा रहे थे वही यह जिम्मेदारी अब भी निभाते रहेंगे। न ही यह कहा गया है कि प्रवक्ताओं की सूची अलग से जारी की जायेगी। यह उल्लेख करना इसलिये आवश्यक हो जाता है की नई कार्यकारिणी घोषित करते हुए जो पत्र जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि पहले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। लेकिन जब से आप हिमाचल में नये सिरे से सक्रिय हुई है उसकी सारी गतिविधियों केवल प्रवक्ताओं के माध्यम से ही सामने आती रही हैं। पार्टी के पदाधिकारियों की अपने तौर पर क्या कारगुजारी रही है वह अभी सामने नहीं आयी है। अभी तक पार्टी के प्रवक्ता भी उस संदेश से आगे नहीं बढ़ पाये हैं जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सामने रखा है। सामान्य तौर पर अब तक का सारा संवाद दिल्ली मॉडल की वकालत से आगे नहीं बढ़ पाया है। दिल्ली में जो सेवाएं लोगों को मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं वह सेवाएं हिमाचल में भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई जायेंगी। इसी केंद्रीय बिन्दु के गिर्द प्रदेश की राजनीति और स्थिति को घुमाने की रणनीति पर काम हो रहा है। किसी भी वेलफेयर स्टेट में जन सुविधाएं जनता को सुगमता से और निशुल्क उपलब्ध होनी चाहिये। कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तो निशुल्क होनी ही चाहिये। लेकिन इसमें प्राइवेट सैक्टर का दखल कहां तक और कितना रहना चाहिये यह भी स्पष्ट होना चाहिये।

हिमाचल में आप शिक्षा को केंद्रीय मुद्दा बनाने की रणनीति पर चल रही है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा पर शिमला में जो संवाद शुरू किया था उसके चक्रव्यूह में प्रदेश सरकार फंस गई है। उसे जवाब देने पर आना पड़ा है अब हमीरपुर में भी केजरीवाल ने उसी संवाद को आंकड़ों सहित आगे बढ़ाया। इसका जवाब सरकार से आता है या नहीं यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन हमीरपुर में जिस तरह से भगवंत मान ने हिमाचल के मिंजर को लेकर अपना ज्ञान लोगों के सामने रखा है उस पर सोशल मीडिया में आ रही प्रतिक्रियाओं ने आप की गंभीरता पर स्वतः ही कई प्रश्न खड़े कर दिये है। यही नहीं इसी अवसर पर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष ने जब यह कहा कि पिछले 75 वर्षों से हिमाचल को मुद्दे ही मिल रहे हैं तो उससे भी यही संदेश गया है कि आप का नेतृत्व अभी तक प्रदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी देश को आजाद हुये ही इतने वर्ष हुये हैं और आप के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरह से भाजपा के ही आरोप को आगे बढ़ाया है कि अब तक देश से लेकर प्रदेश तक जो भी नेतृत्व रहा उसने कुछ नहीं किया है चाहे वह केंद्र में नेहरू काल रहा हो या प्रदेश में डॉ. परमार का।

आप हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस का विकल्प होने का दावा कर रहा है इसलिये उसके नेतृत्व द्वारा कहे गये एक – एक शब्द का आकलन किया जायेगा। उससे प्रदेश को लेकर पूरी जानकारी और समझ होने की अपेक्षा की जायेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व से एक सूत्र तो मिलेगा लेकिन उस पर पूरी इमारत खड़ी करना प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली मॉडल तो सही है लेकिन उसको प्रदेश में व्यवहारिक शक्ल देना यहां बैठे आदमी का काम होगा। फिर दिल्ली की जो स्थिति है वह देश के अन्य किसी राज्य की नहीं है। दिल्ली जितना कर राजस्व किसी अन्य राज्य का नहीं है। हिमाचल के संसाधनों और उनके दोहन तथा उपयोग को लेकर एक ठोस समझ बनानी आवश्यक होगी। यहां पर पिछले कुछ वर्षो में रही सरकारों ने प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है और इसका परिणाम है प्रदेश का कर्जभार 70000 करोड़ के पार हो जाना। आज जयराम सरकार पर सबसे बड़ा आरोप ही यह है कि उसके शासनकाल में कर्ज और बेरोजगारी दोनों इतने बड़े हैं कि शायद यह अपने इतिहास हो जाये। क्योंकि यह दोनों एक साथ तब बढ़ते हैं जब भ्रष्टाचार का आकार इससे भी बड़ा हो जाये। आज हिमाचल में राजनीतिक विकल्प बनने के लिये प्रदेश की इन समस्याओं की प्रमाणिक जानकारी होना और उसे जनता तक ले जाकर जनता को विकल्प की मांग करने तक लाना होगा। लेकिन अभी तक आप से जुड़े किसी भी नेता से यह उम्मीद नहीं बंधी है कि वह भाजपा और कांग्रेस से बेहतर कर पायेगा। यदि आने वाले दिनों में भी आप की गंभीरता इस संदर्भ में सामने नहीं आती है तो उसके लिये अभी दिल्ली दूर है कि कहावत चरितार्थ हो जायेगी।